

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या -46/2019

(अपील संख्या-1946/2002)

गोपाल लाल खण्डेलवाल

-प्रार्थी-अपीलार्थी

बनाम

1. हरेश कुमार शर्मा, निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सोहन लाल चौधरी, अधीक्षक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, वृत्त, बीकानेर।

-अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.04.2022
आदेश की दिनांक : 25.01.2024

उपस्थित :-

प्रार्थी-अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मुकेश जोशी, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. प्रार्थी-अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह अभिकथन किया है कि अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण ने अधिकरण के अपील संख्या 1946/2002 में दिनांक 22.03.2018 को पारित आदेश (अनुलग्नक-1) की पालना आदिनांक तक नहीं की है। अधिकरण के पूर्वोक्त आदेश दिनांक 22.03.2018 का प्रभावी भाग (Operating Part) निम्न प्रकार है :-

"10. उपर्युक्त विवेचनानुसार हस्तगत अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर यह आदेश दिया जाता है कि वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25.01.1992 के अनुसार अपीलार्थी की सेवा की उसकी नियमित नियुक्ति की तिथि से गणना करते हुए उसको निम्नांकित तिथियों से द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान स्वीकृत किये जावें :-

(i)अपीलार्थी की 18 वर्ष की सेवा दिनांक 02.04.1984 को पूर्ण होती है, परन्तु उपर्युक्त विवरणानुसार उसको वर्ष 1979 में 1 वार्षिक वेतन वृद्धि 2 वर्ष के लिए रोकी जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण उसको द्वितीय चयनित वेतनमान 1 वर्ष के विलम्ब से अर्थात् दिनांक 02.04.1985 को देय होगा। इस प्रकार अपीलार्थी दिनांक 02.04.1985 से द्वितीय चयनित वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः उसको दिनांक 02.04.1985 से द्वितीय चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जावे। इसका वास्तविक लाभ दिनांक 25.01.1992 से देय है।

(ii)अपीलार्थी की 27 वर्ष की सेवा दिनांक 02.04.1993 को पूर्ण होती है, परन्तु गत 7 वर्ष में उक्त विवरणानुसार उसके वर्ष 1987-88, 1988-89 एवं 1989-90 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन असंतोषप्रद हैं। इसके अतिरिक्त आदेश दिनांक 02.05.1991 के द्वारा उसकी 3 वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकी गई हैं। इस प्रकार उसको तृतीय चयनित वेतनमान 6 वर्ष विलम्ब से अर्थात् दिनांक 02.04.1999 से देय होगी। अपीलार्थी दिनांक 02.04.1999 से तृतीय चयनित वेतनमान प्राप्त

करने का अधिकारी है। अतः उसको दिनांक 02.04.1999 से तृतीय चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जावे और तदनु रूप समस्त पारिणामिक लाभों (संशोधित सेवानैवृत्तिक परिलाभों सहित) प्रदान किय जावें।"

2. उनका आगे अभिकथन है कि प्रत्यर्थीगण जानबूझ कर अधिकरण के आदेश की पालना नहीं कर रहा है एवं माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 22.03.2018 की बिना उचित कारण के जानबूझ कर अवहेलना की जा रही है, जो कि माननीय अधिकरण के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है एवं माननीय अधिकरण के आदेश की अवहेलना के लिए दोषी है।
3. अतः अवमानना प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि प्रत्यर्थी विभाग से माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 22.03.2018 (अनुलग्नक-1) की पालना करवायी जावे और पालना नहीं करने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही प्रारम्भ कर माननीय उच्च न्यायालय को दण्ड हेतु रैफर किया जावे।
4. अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्ता का कथन है कि अधिकरण के आदेश के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा एक रिव्यू याचिका इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी है, जो वर्तमान में लम्बित है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रिव्यू याचिका के निस्तारण के पश्चात ही आदेश की पालना की जा सकती है।
5. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में आदेश पारित किये गये थे। अपीलार्थी की ओर से जो रिव्यू याचिका प्रस्तुत की गयी है, उसमें केवल मात्र 27 वर्ष के चयनित वेतनमान के सम्बन्ध में रिव्यू याचिका किये जाने की प्रार्थना की गयी है। अतः यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी को 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ भी इस अधिकरण के आदेश के अनुसार पांच वर्ष बाद भी प्रदान नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिकरण के आदेश की आंशिक रूप से भी पालना नहीं की गई है।
6. यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अधिकरण ने प्रार्थी-अपीलार्थी की पूर्वोक्त अपील स्वीकार कर ऊपर वर्णित आदेश के अनुसार अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण को कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। इस प्रकार यह स्वतः स्पष्ट है कि अधिकरण के द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण ने अभी तक नहीं की है। अतः अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण के लिये यह आवश्यक था कि वे अधिकरण के आदेश की समयावधि में पालना करते या माननीय उच्च न्यायालय से इसकी क्रियान्विति पर कोई स्थगन आदेश प्राप्त करते। प्रिवी

काउन्सिल के सर लॉरेन्स जेनकिन्स ने जसकर्ण बोइद बनाम पिरथीचन्द लाल (ए.आई.आर. 1918 पी.सी. 151) के प्रकरण में निम्न प्रकार अवधारित किया था :-

"whatever be the theory under other systems of law, under the Indian law and procedure an original decree is not suspended by the presentation of an appeal nor is its operation interrupted where the decree on appeal is merely one of dismissal. There is nothing in the Indian law to warrant the suggestion that the decree or order of the court or tribunal of the first instance becomes final only on the termination of all proceedings by way of appeal or revision."

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नूह (ए.आई. आर. 1958 एस.सी. 86) में प्रिवी कौंसिल के पूर्वोक्त निर्णय का अनुमोदन करते हुए निम्न मत व्यक्त किया था :-

"the filing of an appeal might put the decree or order in jeopardy but until it is reversed or modified it remains effective."

8. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति पी.डी.देसाई ने हंसराज धीर के प्रकरण (1985 Cri. L. J. 1030) में अवमानना प्रकरण के सिद्धान्तों की निम्न प्रकार व्याख्या की थी :-

"Once a case is decided, it is the bounden duty of the State and its subordinates to implement, with the utmost expedition, the said decision. In a Government which is ruled by law, there must be complete awareness to carry out faithfully and honestly the decisions rendered by courts of law after effective adjudication. Then only will private individuals, organisations and institutions learn to respect the decisions of courts. In absence of such attitude on the part of all concerned, chaotic conditions might arise and the functions assigned to the courts of law under the Constitution might be rendered a futile exercise. It requires to be emphasised, in this connection, that mere preferment of an appeal does not automatically operate as a stay of the decision under appeal and that till an application for stay is moved and granted by the appellate court, or, in the alternative, the court which rendered the decision is moved and grants an interim stay of the decision pending the preferment of an appeal and grant of stay by the appellate court, the decision continues to be operative. Indeed, non-compliance with the decision on the mere ground that an appeal is contemplated to be preferred or is actually preferred, and that, therefore, the matter is subjudice, may amount to contempt of court punishable under the Contempt of Courts Act, 1971."

9. उक्त विनिश्चयों के आलोक में और प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विनम्र मतानुसार यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण ने इस अधिकरण के आदेश दिनांक 22.03.2018 की पालना न कर उक्त न्यायिक आदेश की अवमानना कारित की है। हम इस अवमानना प्रकरण को अधिकरण में लम्बित रखना उचित नहीं समझते हैं और इस प्रकरण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को Contempt of Courts Act, 1971 की धारा 10 के प्रावधान के क्रम में उपर्युक्त अवमानना कृत्य के लिए

अवमाननाकर्ताओं के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु संदर्भित करना उचित समझते हैं।

10. उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी-अपीलार्थी के अवमानना प्रार्थना पत्र पर अधिकरण के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 10 के अन्तर्गत अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ, जयपुर को संदर्भित करावें। अपीलार्थी के अधिवक्ता को आदेश दिया जाता है कि वो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में उपस्थित हों।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)